गपशप

आईपीएल में लालू-पुत्र

आईपीएल पर सबसे नाराज़ हैं लालू जी। उनका कहना है कि उनका बेटा तेजप्रताप आईपीएल में दो साल पहले बिका था, लेकिन अभी तक उसे खेलने का मौका नहीं दिया गया। उसे तौलिया लेकर दौड़ाया जाता है और वह खिलाड़ियों के पसीने पोछता है और उन्हें पानी पिलाता है। लानत है इस पर कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा खिलाड़ियों के पसीने पोछे और पानी पिलाये। पर आईपीएल लालू की किचन कैबिनेट तो है नहीं कि एक समय जब लालू की चलती थी तब जिसे राजनीति का थोड़ा ज्ञान भी न हो, अपनी उस पत्नी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। अपनी प्रेमिका को केंद्र में कोयला मंत्री बनवा दिया। यह तो आईपीएल है। लालू को बड़ी शर्म आती है कि उनका बेटा-एक राजा (अब भूतपूर्व) का बेटा खिलाड़ियों के पसीने पोछे। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। वैसे खेलने में तो फिसड्डी था उनका राजकुमार, पर राजनीतिक पैरवी भिड़ा कर उसे बेच दिया। अब वापस भी नहीं बुला सकते, क्योंकि वह बिका हुआ है और उसके मालिकान उससे जो चाहे काम ले सकते हैं। खेल नहीं सकता तो खिलाड़ियों के पसीने ही पोछे। एक काम और कर सकता है। दुनिया के बड़े-बड़े खिलाड़ियों के साथ अपने फोटो छपवा सकता है, उनसे ऑटोग्राफ आदि ले सकता है।

क्रिकेट ने कहीं का नहीं छोड़ा

थरूर को यह गरूर था कि वे चाहे जो भी करें, कोई उनका बाल-बांका तक नहीं कर सकता। इसी गरूर में उन्होंने आईपीएल में अपनी मनमानी करनी चाही। आईपीएल के क्रिकेट उद्योग में अपनी प्रेमिका के नाम से करोड़ों के शेयर बिना किसी भुगतान के ले लिये। जब इस पर शोर-शराबा मचा तो थरूर ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्होंने कोई ग़लत काम नहीं किया है। लेकिन विरोधी दल वाले उनका इस्तीफ़ा मांग रहे थे। प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर थे। सोनिया गांधी बार-बार आग्रह करने के बावजूद मिलने का समय नहीं दे रही थीं। आखिर थरूर जब काफ़ी शर्मिन्दा हो लिए तो मिलने का समय दिया और जम कर झाड़ पिलाई। पूर्व डिप्लोमेट थरूर साहब की बोलती बंद हो गई। त्राहिमाम करते हुए थरूर 'क्रिकेट मंत्री' शरद पवार के पास गये, पर उन्होंने भी आड़े वक्त पर मुंह फेर लिया। सोनिया ने इस्तीफ़ा देने का 'आदेश' दिया था। सो प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे से वापस आते ही इस्तीफ़ा दे दिया और गम ग़लत करने वाली दवा लेकर बैठ गये। फ़िर पुष्कर की याद में तड़प-तड़प कर दिल को चाक करते रहे।

क्रिकेट का नंगा नाच

आईपीएल कांड उजागर होने के बाद अच्छे-अच्छे पिटते नज़र आ रहे हैं शरद पवार से लेकर पटेल तक। आईपीएल की टीमों के मालिक इस देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों से लेकर फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियां भी हैं। पैसा कमाने की हवस इस कदर बढ़ गई कि कुछ न सोचा और न समझा और देशी-विदेशी खिलाड़ियों को नीलामी में खरीद कर टीमों के मालिक बन गये। पर पूंजीपति खुश हैं कि उनका बाल बांका तक नहीं होना है, लेकिन शाहरुख खान जैसे लंपट फंस सकते हैं। शिल्पा जैसी '70 चूहे खा कर हज कर चुकी' पूर्व अभिनेत्री फंस सकती है। आयकर वालों ने अब जगह-जगह छापा मारने की तैयारी कर ली है और छापा मार भी रहे हैं। पहले से इन्हें ध्यान नहीं था। इधर बंगाल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और भारतीय बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जगमोहन डालमिया को यह पता ही नहीं कि सैंकड़ों करोड़ रुपये उनके बोर्ड में कैसे चले आये। बड़े ही मासूम बन गये जनाब। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान ने जो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के मालिक हैं, उन्हें रकम भेजी थी मैच के आयोजन के लिए। इधर मोदी अपनी गर्दन बचाने के लिए बड़े अंबानी की शरण में जा रहे हैं, क्योंकि समझा जाता है कि उनकी सोनिया गांधी तक अच्छी पैठ है। पर गर्दन बचने की नहीं। बड़े अंबानी मुंबई इंडियंस टीम के मालिक हैं। बंगलौर टीम के मालिक शराब किंग विजय माल्या है। सभी बड़े-बड़े लुटेरे क्रिकेट के इस नंगे नाच में शामिल हैं।

माकपा के 'सरकारी नेता'

हरियाणा के सर्वकर्मचारियों के नेता को अचानक माओवाद का दौरा पड़ने लगा है। जनाब हर कहीं यही कह रहे हैं कि माओवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस बात को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कई बार कह चुके हैं। फ़िर सर्वकर्मचारी नेता इसे लगातार क्यों दुहरा रहे हैं, समझ में नहीं आता। खास बात यह है कि माओवादी हिंसा की ताजी और सबसे बड़ी घटना जहां हुई, उस छत्तीसगढ़ का जिक्र तक नहीं करते और यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में माओवाद के मारे माकपा की नाक में दम है। न जाने कितने माकपा कार्यकर्ता मारे गये हैं। इसके लिए वे ममता बनर्जी को भी जिम्मेदार ठहरा हैं। सर्वकर्मचारी नेता की लोकल मीडिया में अच्छी-खासी पैठ है। वे कुछ कहते नहीं कि मीडिया वाले लोक लेते हैं। इस वजह से जनाब बहुत मौज में हैं और जहां भी संभव होता है, माओवादी आतंक का उल्लेख करना नहीं भूलते। अब पूछा जा सकता है कि भला बंगाल से उनका यह रिश्ता कैसा है? दरअसल उनका रिश्ता माकपा से है। वे माकपा के 'सरकारी नेता' हैं।

गुरु जी की गद्दी डोली

महाभ्रष्ट, रिश्वतखोर, हत्यारे शिबू सोरेन की गद्दी फिर डोल रही है। गुरु जी भाजपा के समर्थन से झारखंड सरकार चला रहे हैं। समर्थन तो भाजपा का लिया और खुद समर्थन कांग्रेस का किया। सवाल है, आखिर भाजपा ने इन्हें समर्थन दिया ही क्यों? क्या भाजपा को नहीं मालूम था कि यह डाकू केंद्र सरकार में कोयला मंत्री बना बैठा था। जब संप्रग का मुख्यमंत्री मधु कोडा अरबों की लूट में फंसा तो उसे गद्दी छोड़नी पड़ी और तब सोनिया के 'आशीर्वाद' से गुरु जी गद्दी पर बैठा। अब वह कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं करता? कुल मिला कर इसका समर्थन कर भाजपा ने भी यह एक बार फिर साबित कर दिया कि वह हत्यारों और डाकुओं की पक्षधर है। इस पर जनाब गडकरी साहब क्या कहना चाहेंगे?

● फ़ोन टैपिंग

आईपीएल घोटाले से ध्यान हटाने का साधन मात्र

23 अप्रैल को यकायक सभी प्रचार माध्यमों द्वारा फ़ोन टैपिंग का मामला उछाल दिया गया। बताया गया कि देश के पांच बड़े-बड़े नेताओं (नीतीश कुमार, प्रकाश करात, शरद पवार मुलायम सिंह यादव और शरद यादव) के फ़ोन बरसों से टैप हो रहे हैं।

फ़ोन टैप करने का धंधा कोई नया निराला काम नहीं है। जब से खुफ़िया एजेंसियां बनी हैं तब से ये काम होते आ रहे हैं। जब टेलिफ़ोन नहीं होते थे तब भी गुप्तचर चोरी-छिपे बातों को टैप किया करते थे, लेकिन टेलिफ़ोन का आविष्कार होने के बाद तो गुप्तचरों का काम और भी आसान हो गया। अरबों रुपयों के बजट से चलने वाले गुप्तचर विभाग यदि फ़ोन भी टैप नहीं करेंगे तो क्या वे मंदिर-गुरुद्वारों में कीर्तन करेंगे? इन विभागों के पास आज ऐसी-ऐसी तकनीक आ चुकी हैं कि बिना किसी टेलिफ़ोन एक्सचेंज की सहायता के भी ये लोग़ फ़ोन टैप कर सकते हैं। लाखों-करोड़ों रुपये के खर्च से आने वाली तकनीक एवं मशीनें ये लोग़ अपने वेतन से तो लाने से रहे, जाहिर है यह सब सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती हैं। और सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सबको इनकी आवश्यकता रहती है। यहां प्रश्न यह पैदा होता है कि प्रकाश करात, शरद यादव, नीतीश कुमार के फ़ोन टैप से निकलेगा क्या? न तो ये किसी आतंकवादी गिरोह से जुड़े हैं और न किसी अपराधी गिरोह से, सरकार विरोधी इनकी जो भी बातें अथवा योजनायें हैं, वे सब सर्वविदित एवं घोषित हैं। समझा जा रहा है कि करात की फ़ोन टैपिंग यूपीए सरकार ने अपनी पहली पारी में उस वक्त कराई थी जब वे सरकार का समर्थन तो कर रहे थे, लेकिन परमाणु मामले पर समर्थन वापस लेने की बात कर रहे थे। लेकिन इतनी पुरानी बीत चुकी बात, जिसका आज कोई महत्त्व नहीं है, यकायक उठाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जाहिर है, आईपीएल क्रिकेटेनमेंट के महाघोटाले से ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा पक्ष और विपक्ष, दोनों की सहमति से उठाया गया है। सर्वविदित है कि इस घोटाले में क्या कांग्रेसी, क्या भाजपाई, क्या एनसीपी, सभी तो इनमें शामिल हैं। ऐसे में इन सभी नेताओं व इनके पूंजीपति आकाओं की यही कोशिश रही कि मीडिया पर सारा दिन बज रहे आईपीएल के ढोल को किसी तरह तो बंद किया जाये। सो फ़ोन टैपिंग को आईपीएल से बड़ा ढोल बना कर बजवाने की कोशिश की, लेकिन वह महज झुनझुना साबित हुआ। लालू ने तो सदन में साफ़ ही कह दिया कि छोड़ो इस टैपिंग-वैपिंग को, आईपीएल पर बात करते हैं।

> **आईपीएल क्रिकेटेनमेंट के महाघोटाले से ध्यान हटाने के लिए यह मुद्दा पक्ष और विपक्ष, दोनों की सहमति से उठाया गया है। सर्वविदित है कि इस घोटाले में क्या कांग्रेसी, क्या भाजपाई, क्या एनसीपी, सभी तो इनमें शामिल हैं। ऐसे में इन सभी नेताओं व इनके पूंजीपति आकाओं की यही कोशिश रही कि मीडिया पर सारा दिन बज रहे आईपीएल के ढोल को किसी तरह तो बंद किया जाये।**

-विशेष प्रतिनिधि

लाइसेंसी हथियार ज़ब्त होते हैं केवल शरीफ़ों के

पूर्व ज़िला पुलिस अधीक्षक आलोक मित्तल की सिफ़ारिश पर तत्कालीन ज़िला मैजिस्ट्रेट बिजेन्द्र सिंह ने अपने आदेश नंबर-210-212 पीएलए दिनांकित 24.3.08 के द्वारा सेक्टर-9 के निवासी विकास चौधरी का शस्त्र लाइसेंस नं.18/07 रद्द कर के पुलिस को आदेश दिया था कि वह विकास चौधरी द्वारा रखे जा रहे लाइसेंसी हथियार को ज़ब्त करे। उक्त आदेश गत दो वर्षों से थाना सेक्टर-7 व इसकी चौकियों में भटकता फ़िर रहा है, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं कर रहा।

इससे भी अधिक मजे की बात यह है कि रद्द हो चुके इस लाइसेंस की मियाद 7.3.10 तक की ही थी। इसे रिन्यू कराने के लिए विकास ने बाकायदा आवेदन कर दिया है और बैंक में 60 रुपये बतौर रिन्यूल फ़ीस भी जमा करा दी है। अब उसका आवेदन गत दो माह से थाना सेक्टर-7 में पुलिस रिपोर्ट के लिए पड़ा है। यदि सब कुछ यूं ही चलता रहे तो उसका रद्द लाइसेंस रिन्यू होना भी निश्चित है।

दूसरी मज़े की बात यह है कि आये दिन पुलिस किसी न किसी बहाने लाइसेंसी हथियार जमा कराने के आदेश जारी करती रहती है, जिसकी पालना सभी शरीफ़ लोग़ करते हैं, लेकिन पुलिस के आशीर्वाद से विकास ने कभी अपना हथियार जमा नहीं करवाया। विदित है कि पुलिस अधीक्षक यूं ही बैठे-बिठाये किसी का शस्त्र लाइसेंस रद्द नहीं किया करते। पुलिस द्वारा इस तरह के आदेश केवल शातिर अपराधियों के मामले में ही जारी किये जाते हैं।

मज़दूर मोर्चा के 1-15 अप्रैल, 2010 के अंक में प्रकाशित किया गया था कि अक्टूबर में राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनज़र ज़िला पुलिस ने आदेश जारी किया हुआ है कि 31.3.10 तक सभी लाइसेंसी हथियार जमा करा लिये जायें। इससे पहले चुनावों के दौरान भी ऐसे ही आदेश लागू थे। यह एक विडंबना है कि जो शरीफ़ नागरिक आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहते हैं, उनसे तो पुलिस शस्त्र जमा करा लेती है और जो लोग़ खुद समाज के लिए ख़तरा हैं, उनके हथियार जमा कराने में पुलिस की कोई रुचि नहीं रहती, ऐसे में उन्हें निहत्थे लोग़ों पर पर हमले करने की पूरी छूट होती है। इसे पुलिस द्वारा अपराधियों को खुला संरक्षण नहीं तो और क्या कहेंगे? जाहिर है, ऐसा संरक्षण मुफ़्त में तो मिलता नहीं।

> **मज़दूर मोर्चा के 1-15 अप्रैल, 2010 के अंक में प्रकाशित किया गया था कि अक्टूबर में राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनज़र ज़िला पुलिस ने आदेश जारी किया हुआ है कि 31.3.10 तक सभी लाइसेंसी हथियार जमा करा लिये जायें। इससे पहले चुनावों के दौरान भी ऐसे ही आदेश लागू थे। यह एक विडंबना है कि जो शरीफ़ नागरिक आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखना चाहते हैं, उनसे तो पुलिस शस्त्र जमा करा लेती है और जो लोग़ खुद समाज के लिए ख़तरा हैं, उनके हथियार जमा कराने में पुलिस की कोई रुचि नहीं रहती, ऐसे में उन्हें निहत्थे लोग़ों पर पर हमले करने की पूरी छूट होती है। इसे पुलिस द्वारा अपराधियों को खुला संरक्षण नहीं तो और क्या कहेंगे? जाहिर है, ऐसा संरक्षण मुफ़्त में तो मिलता नहीं।**